

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] No. 260] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14,1937 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जून, 2015

सं. टीएएमपी/29/2015-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शिंक्यों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण इसके द्वारा, इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार, आयात सामान्य मालसूची (आईजीएम) अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में कार्गों के रुप में मालसूची में विनिर्दिष्ट अपनी प्रथम यात्रा पर जाने वाले पोतों पर घाट शुल्क का प्रभार लगाने के लिए विद्यमान दर मानों में संशोधन के लिए चैन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के प्रस्ताव का निपटान करता है।

महा पत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/29/2015-सीएचपीटी

चैन्नई पत्तन न्यास

आवेदक

कोरमः

- (i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

2460 GI/2015 (1)

चैन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ने अपने दिनांक 14 जनवरी 2015 के पत्र द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है:

- (क) क्या चैन्नई पत्तन किसी पोत को कार्गों के रूप में समझना और विद्यमान दर मानों में घाट शुल्क की परिभाषा पर विचार करते हुए घाट शुल्क लगाना जारी रख सकता है, यदि यह कस्टम में दायर आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में एक कार्गों के रूप में विनिर्दिष्ट है।
- (ख) पोत को वाहन के रूप में व्यवहृत करते हुए यदि उसे आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में एक कार्गों के रूप में विनिर्दिष्ट किया भी जाए तो भी क्या चैन्नई पत्तन को किसी पोत को कार्गों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- 2. कानूनी परामर्श के आधार पर हमारे पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा सीएचपीटी को यह स्पष्ट किया गया था कि पोत, जो सीएचपीटी पर आते हैं, जिनके लिए कस्टम अधिनियम,1962 के प्रयोजन से आईजीएम और/अथवा ईजीएम दायर किए जाते हैं, को 'कार्गों' के रुप में नहीं माना जा सकता है; और वे केवल वाहन हैं; और सीएचपीटी को ऐसे पोत पर घाट शुल्क नहीं लगाना चाहिए और जहां तक मांगे गए स्पष्टीकरण का संबंध है, उल्लेख है कि ऐसे पोत केवल वाहन हैं न कि कार्गो।
- 3.1 इस बैकड्रोप में, सीएचपीटी ने अपने दिनांक 18 अप्रैल 2015 के पत्र द्वारा आयात सामान्य मालसूची (आईजीएम) अथवा निर्यात सामान्य मालसूची (ईजीएम) में कार्गों के रूप में मालसूची में विनिर्दिष्ट अपनी प्रथम यात्रा पर जाने वाले पोतों पर घाट शुल्क का प्रभार लगाने के लिए विद्यमान दर मानों में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- 3.2. सीएचपीटी के दिनांक 18 अप्रैल 2015 के पत्र में विनिर्दिष्ट प्रमुख मुद्दे संक्षेप में इस प्रकार हैं:
 - (i) वर्तमान में, जब किसी पोत को उसकी पहली यात्रा पर आईजीएम/ईजीएम में कार्गो के रूप में घोषित किया जाता है, तो उसे कार्गो के रूप में माना जाता है और सीएचपीटी के दर मानों के अध्याय-। के खण्ड 1.1. (vi) के अंतर्गत निर्धारित घाट शुल्क की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए घाट शुल्क की वसूली की जाती है।
 - (ii) कुछ पोत अभिकर्ताओं ने सीएचपीटी को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि ऐसे पोतों को कार्गो के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इन्हें एक वाहन के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए पोत पर घाट शुल्क का प्रभार लगाना अपने आप में ठीक नहीं है।
 - (iii) उपर्युक्त को देखते हुए, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 14.1.2015 द्वारा इस प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए अन्रोध किया है:
 - (क) क्या चैन्नई पत्तन पोत को कार्गों के रूप में व्यवहृत और विद्यमान दर मानों में घाट शुल्क की परिभाषा पर विचार करते हुए घाट शुल्क लगाना जारी रख सकता है, यदि यह कस्टम में दायर आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में एक कार्गों के रूप में विनिर्दिष्ट हो।

अथव

- (ख) पोत को वाहन के रूप में व्यवहृत करते हुए यदि उसे आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में एक कार्गों के रूप में विनिर्दिष्ट किया भी जाए तो भी क्या चैन्नई पत्तन को किसी पोत को कार्गों के रूप में व्यवहृत नहीं किया जाना चाहिए।
- (iv) टीएएमपी ने अपने पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिए हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो पोत सीएचपीटी पर आते हैं, जिसके लिए कस्टम अधिनियम, 1962 के प्रयोजन से आईजीएम और/अथवा ईजीएम दायर किए जाते हैं, उन्हें 'कार्गों' के रुप में नहीं समझा जा सकता है; और वे केवल वाहन हैं; और सीएचपीटी ऐसे पोतों पर घाट शुल्क की वसूली नहीं करेगा।
- (v) इस प्रकार, टीएएमपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर, सीएचपीटी ने सीएचपीटी के दर मानों में एक नया नोट सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव किया है और स्पष्ट स्थिति उपलब्ध कराने की दृष्टि से अध्याय -III –

कार्गों से संबंधित प्रभार के स्केल-1-घाट शुल्क के अंतर्गत विद्यमान नोट संख्या (9) के पश्चात निम्नलिखित नोट सम्मिलित करने का प्रसताव किया गया है:

- "(10) अपनी प्रथम यात्रा पर पत्तन में आने वाले पोतों, जिन्हें कस्टम अधिनियम, 1962 के प्रयोजन से आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में कार्गों के रूप में घोषित किया गया हो, को कार्गों के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे पोतों पर कोई घाट शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यदि ये पोत पत्तन में अपने स्वयं के प्रयासों से आते हैं और अपने स्वयं के प्रयासों से पत्तन सीमाओं से बाहर जाते हैं। तथापि, जब पत्तन सीमाओं के भीतर पोतों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग का कार्य किया जाता है, ऐसे पोतों पर उपर्युक्त मान-1 के अनुसार घाट शुल्क देय होगा।"
- (vi) इस प्राधिकरण से सीएचपीटी के विद्यमान दरमानों में उपर्युक्त नोट को समाहित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है और इस उपर्युक्त संशोधन (10) को प्रवृत्त करने की तारीख भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।
- 4.1. कानूनी परामर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित अध्याय-III– कार्गो से संबंधित प्रभार के घाट शुल्क मान-1 के अंतर्गत विद्यमान नोट संख्या (9) के पश्चात नोट संख्या (10) के रुप में निम्नलिखित का समावेश करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करता है:
 - "(10) अपनी प्रथम यात्रा पर पत्तन में आने वाले पोतों, जिन्हें कस्टम अधिनियम, 1962 के प्रयोजन से आयात सामान्य मालसूची अथवा निर्यात सामान्य मालसूची में कार्गों के रूप में घोषित किया गया हो, को कार्गों के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे पोतों पर कोई घाट शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यदि ये पोत पत्तन में अपने स्वयं के प्रयासों से आते हैं और अपने स्वयं के प्रयासों से पत्तन सीमाओं से बाहर जाते हैं। तथापि, जब पत्तन सीमाओं के भीतर पोतों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग का कार्य किया जाता है, ऐसे पोतों पर उपर्युक्त मान-1 के अनुसार घाट शुल्क देय होगा।"
- 4.2. जहां तक, इसके द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख का संबंध है, यह उल्लेख करना है कि इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतया गजट अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के समाप्त होने के पश्चात प्रवृत्त होने की प्रत्याशा होती है, जब तक कि अन्यथा संबंधित प्रशुल्क आदेशों में विशिष्ट रुप से कोई अलग व्यवस्था न की जाए। अपवाद स्वरुप के मामलों में, पूर्व प्रभाव से प्रवृत्त होने के कारणों को दर्ज किया जाएगा। यह विचारणीय है कि सीएचपीटी ने दिनांक 25 मार्च, 2015 के पत्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर संदर्भाधीन प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया है। चूंकि 25 मार्च 2015 को स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए, प्रस्तावित संशोधन 25 मार्च 2015 (सीएचपीटी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तारीख होने के कारण) से प्रवृत्त करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 143 / 2015(97)]

Tariff Authority for Major Ports

Mumbai, the 2nd June, 2015

NOTIFICATION

No.TAMP/29/2015-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Chennai Port Trust (CHPT) for amending its existing Scale of Rates for levy of wharfage on Vessels manifested as cargo in the Import General Manifest (IGM) or Export General Manifest (EGM) on her first voyage, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/29/2015-CHPT

Chennai Port Trust ... Applicant

QUORUM:

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of May 2015)

The Chennai Port Trust (CHPT), vide its letter dated 14 January 2015 had sought the following clarification:

- (a) whether the Chennai Port can continue to treat the vessel as a cargo if it is manifested as a cargo either in the Import General Manifest or Export General Manifest filed with Customs and levy wharfage considering the definition of wharfage in the existing Scale of Rates.
- (b) whether the Chennai Port should not treat the vessel as cargo even if it is manifested as a cargo either in the Import General Manifest or Export General Manifest treating the vessel as conveyance.
- 2. Based on the legal opinion, it was clarified to the CHPT vide our letter dated 25 March 2015 that vessels which call at CHPT, for which IGMs and/ or EGMs are filed for the purposes of Customs Act, 1962, cannot be treated as 'cargo'; and they are conveyance only; and, the CHPT should not charge wharfage on such vessels and that in relation to the clarification sought, such vessels are conveyance and not cargo.
- 3.1. In this backdrop, the CHPT vide its letter dated 18 April 2015 has submitted a proposal for amending its existing Scale of Rates for levy of wharfage on Vessels manifested as cargo in the Import General Manifest (IGM) or Export General Manifest (EGM) on her first voyage.
- 3.2. The main points made by the CHPT in its letter dated 18 April 2015 are summarized below:
 - (i) At present, when a vessel is declared as cargo in the IGM / EGM on her first voyage, the same is treated as cargo and wharfage is collected, taking into account the definition for wharfage prescribed under clause 1.1. (vi) of Chapter-I of the Scale of Rates of CHPT.
 - (ii) Some of the vessel agents represented to CHPT that such vessels should not be treated as cargo and it should be treated as a conveyance and hence levy of wharfage on vessel itself is not correct.
 - (iii) In view of the above, the CHPT *vide* its letter dated 14.1.2015 had requested the Authority to clarify:
 - (a) whether the Chennai Port can continue to treat the vessel as a cargo if it is manifested as a cargo either in the Import General Manifest or Export General Manifest filed with Customs and levy wharfage considering the definition of wharfage in the existing Scale of Rates

or

- (b) whether the Chennai Port should not treat the vessel as cargo even if it is manifested as a cargo either in the Import General Manifest or Export General Manifest treating the vessel as conveyance.
- (iv) The TAMP vide its letter dated 25 March 2015 has furnished clarification stating that the vessels which call at the CHPT, for which IGMs and/or EGMs are filed for the purposes of Customs Act, 1962, cannot be treated as 'cargo'; and they are conveyance only; and the CHPT should not charge wharfage on such vessels.
- (v) Thus, on the basis of the clarification furnished by the TAMP, the CHPT proposes to include a new note in the Scale of Rates of CHPT and in order to provide clarity, it is proposed to incorporate the following note after the existing Note No.(9) under Scale-1 – Wharfage of Chapter-III – Cargo Related Charges:
 - "(10) Vessels calling the Port on her first voyage, which are declared as cargo in the Import General Manifest or Export General Manifest for the purposes of Customs Act, 1962, shall not be treated as cargo and no wharfage shall be levied on such vessels, if the vessels come into the port on their own steam and sail out of the port limits on their own steam. However,

when loading or unloading of vessels takes place within the Port limits, wharfage as per Scale-1 above shall be payable on such vessels."

- (vi) The Authority is requested to approve the incorporation of the above note in the existing Scale of Rates of CHPT and is also requested to clarify the date of effect of this amendment (10) above.
- 4.1. Based on the legal opinion, this Authority is inclined to approve insertion of the following as Note no. (10) after the existing Note No.(9) under Scale-1 Wharfage of Chapter-III Cargo Related Charges, as proposed by the CHPT:
 - "(10) Vessels calling the Port on her first voyage, which are declared as cargo in the Import General Manifest or Export General Manifest for the purposes of Customs Act, 1962, shall not be treated as cargo and no wharfage shall be levied on such vessels, if the vessels come into the port on their own steam and sail out of the port limits on their own steam. However, when loading or unloading of vessels takes place within the Port limits, wharfage as per Scale-1 above shall be payable on such vessels."
- 4.2. With regard to the date of effect of the amendment proposed by it, it is to state that the Order of this Authority generally takes effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases retrospective effect is given for reasons to be recorded. It is noteworthy that the CHPT has mooted the proposal in reference based on the clarification given vide letter dated 25 March 2015. Since a clarification has already been given on 25 March 2015, it is felt appropriate to give effect to the proposed amendment with effect from 25 March 2015 (being the date when the clarification has been furnished to CHPT).

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2015(97)]